(b) the details of the steps taken by the Central Government to meet the shortage of drinking water in Andhra Pradesh; and

(c) by when the Central Government propose to ensure the required supply of drinking water to the affected villages of Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHAN POOJARY): (a) As on 1-4-1989, all problem villages in Andhra Pradesh have been covered fully or partially with safe drinking water facilities.

(b) The Central Government is giving grants-in-aid to the State Government under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) for supply of safe drinking water in rural areas. The Central assistance provided to Andhra Pradesh during VII Plan as under:

	Release under ARWSP (Rs. in crores)
1985-86	15.81
1986-87	17·60
1987-88	24·93
1988-89	26.04
1989 90	23.01 (Rs. 11.51 crores (Allocation released)

Under the National Drinking Water Mission, three districts namely, Kurnool, East Godavari and Mehboobnagar have been taken up as Mini Mission Project areas for pilot studies. Funds amounting to Rs. 2.06 crores, Rs. 85 lakhs and Rs. 85 lakhs have already been released to these districts respectively.

In addition, funds amounting to Rs. 109 lakhs have also been released to the State Government for taking up schemes for water harvesting structures in various districts. Rs. 25 lakhs was released in 1988-89 for conversion of step wells into sanitary wells under the submission on eradication of guinea-worm.

Assistance of Rs. 2.62 lakhs was also released as first instalment of funds for setting up three district level laboratories in Kurnool, East Godavari and Mehboobnagar for water quality monitoring.

The Central Government is also assisting the State Government for setting up 18 desalination plants and 30 defluridation plants.

(c) Partially covered problem villages in the State are likely to be provided with additional sources of safe drinking water supply within the constraint of Plan resources by March, 1990. Augmentation works in the remaining villages will be continued in the Eighth Plan.

दिल्ली में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या

546. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को रोजगार और आजीविका दिलाये जाने से संबंधित सरकार की योजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें कितने नेत्रहीन व्यक्ति 18-35 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) से (ग) 1981 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली से दृष्टि बाधितार्थों की प्रचलन दर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 419 थी शहरी क्षेत्रों में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 173 थी।

केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" तथा "घ" पदों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के तुलनात्मक पदों में 3% रिक्तियां विकलांगों-नेत्रहीनों, बधिरों तथा अस्थि विकलांगों प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत के लिए आरक्षित की गई है।

नेत्रहीनों सहित, केवल विकलांगों को लाभदायक रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए, विकलांगों के लिए 22 विशेष रोजगार केन्द्र तथा 42 विशेष सैल स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी विकलांगों को उपयुक्त रोजगार तलाश करने में सहायता प्रदान करते हैं ।

विकलांगों की अविशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा उन्हें रोजगार पर लगाने के लिए सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत वे नेत्रहीनों सहित विकलांगों को लाभकर रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 9वीं कक्षा से आगे पढ़ने के लिए विकलांगों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं । विकलांगों को दैनिक सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए भी स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से अनुदान दिये जाते हैं । दृष्टि बाधितों को शैक्षिक उपकरण जैसे ब्रेल स्लेट, बेल प्लेट फ्रेम, सिलाई तथा हाई स्कूल छात्रों के लिए कैसेट टेप प्रदान किए जाते हैं ।

संबंधित व्यवसाय में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को सूक्ष्मदर्शी यन्त्र, परकार (कैलीपर्स) इत्यादि जैसे ब्रेल लेखी उपकरण दिए जाते हैं । सामान्य कक्षाओं के छात्रों को ब्रेल लेखन तथा टेपरिकार्डर प्रदान किए जाते हैं ।

निम्नलिखित के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाता है :—

(क) बिक्री स्टालों, खोखों तथा छोटी दुकानों का आवंटन ;

(ख) ब्याज की रियायती दर की योजना के अंतर्गत ब्याज की सामूली दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण ;

(ग) "शिक्षित युवकों को रोजगार" की योजना के अंतर्गत 35,000/— रु० तक के ऋण दिए जाते हैं ।

दृष्टि बाधितों के आयुवार ब्यौरे हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं ।

Resettlement and unauthorised colonies and urban villages with sewer lines in Delhi

547. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of resettlement and unauthorised colonies and urban villages in Delhi and how many have sewer lines:

(b) the quantum of sewage carried daily into the river Yamuna in Delhi and what is the arrangement to check the sewage from falling into the river; and

(c) whether Government have taken any preventive steps to stop the spread of dangerous diseases and epidemics as a result thereof and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Import of Rice and Wheat

548. SHRI P. N. SUKUL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the U.N. Food and Agriculture Organisation has forecast that India would import sizeable amounts of rice and wheat this year;

(b) if so, whether this forecast represents the correct position;

(c) the need of such sizeable imports of rice and wheat, in the face of bumper production of crops this year;

(d) whether these imports are necessitated by the fact that Government's procurement policy failed to show expected results; and

(e) the steps being taken to improve the position and reduce imports of foodgrains?